

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2414
13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

†2414. श्री पी. सी. मोहन:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत देश भर में शहरी गरीबों के बीच कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए की गई/की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है और इस मिशन के अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(ख) सरकार द्वारा देश भर में डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत ऋण और बाजारों तक पहुंच की कमी जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इस योजना की पहुंच और प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत बेंगलुरु में शहरी स्व-सहायता समूहों को सहायता प्रदान करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपायों को कार्यान्वित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है, जिसे फरवरी 2016 से 30 सितंबर, 2024 तक कार्यान्वित किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार से जोड़कर गरीबी और असुरक्षा को कम करना था, परिणामस्वरूप इसके विभिन्न घटकों के

माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सराहनीय सुधार होगा। इस मिशन के तहत देश भर में 30.09.2024 तक हासिल की गई उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	उपलब्धियां
गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या	10,02,545
परिक्रामी निधि पाने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या	6,79,705
कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	15,42,952
रोजगार प्राप्त कुशल उम्मीदवारों की संख्या	8,43,299
व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	9,81,899
बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों को संवितरित ऋणों की संख्या	6,42,207

(ख): योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में किए गये उपायों के साथ देश भर में डीएवाई-एनयूएलएम के तहत ऋण और बाजार तक पहुंच की कमी जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत शहरी स्वयं सहायता समूहों को सहायता देने तथा बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने की पहल की है। जन-सामान्य को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए दो अक्का (एकेकेए) कैफे शुरू किए गए हैं, जिनका संचालन स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में 19 महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को बेकरी उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है।

"दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन" के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2414 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

इस योजना की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अन्य यूएलबी के साथ बेंगलुरु में किए गए उपाय के साथ देश भर में डीएवाई-एनयूएलएम के तहत ऋण और बाजार तक पहुंच की कमी जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- स्वरोजगार कार्यक्रम सहित आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) द्वारा बैंक और शाखावार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं।
- एसएलबीसी, जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (डीएलबीसी) और ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) के साथ बैठकें आयोजित करना।
- बैंकों के साथ एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) ऋण लिंकेज मेलों का आयोजन करना।
- स्वयं सहायता समूहों के लिए विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु स्वयं सहायता समूहों की प्रदर्शनी-सह-बिक्री कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन विपणन रणनीतियों के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचने के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता प्रदान करना।
- राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ मिशन की प्रगति की समीक्षा करना।
- इसके अलावा, राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्नाटक पथ-विक्रेता (आजीविका संरक्षण, स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन और लाइसेंसिंग) योजना, 2020 के अनुपालन में बीबीएमपी सहित कर्नाटक में पथ-विक्रेताओं की पहचान के लिए ऐप आधारित सर्वेक्षण आयोजित किया गया है।
- विभिन्न आईईसी गतिविधियों जैसे होर्डिंग्स, बैनर, पैम्फलेट और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।